ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास

2306. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कर और उन्हें ग्रामीण उद्योगों के रूप में विकसित कर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय और विदेशी बहुद्देशीय कंपनियों को पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई है, यदि हां, तो उन कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक अनुमति प्रदान की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण आय में वृद्धि करना और ग्रामीण रोजगार में अत्यधिक वृद्धि करने की व्यवस्था करना शामिल है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों और कार्य-कलापों का उद्देश्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को पहले उपलब्ध कराई जा चुकी सुविधाओं के अलावा 1989-90 के बजट प्रस्तावों में कुक्कुट दाने के अवयवों पर आयात शुल्क में कमी करना , रेफ्रिजेरेटिड ट्रांसपोर्ट की मशीनरी पर उत्पाद शुल्क में कमी करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुछ उपकरणों पर सीमा शुल्क में कमी करना शामिल है ।

(ग) जुलाई, 1988 से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विदेशी सहयोग करने से संबंधित 14 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है ।

मौजूदा बीज आयात नीति में परिवर्तन

2307. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि वैज्ञानिकों की ओर से सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि मौजूदा बीज आयात नीति में परिवर्तन किया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन वैज्ञानिकों के विचार में इस नीति से हमारा स्वदेशी बीज उत्पादन प्रभावित हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन वैज्ञानिकों से इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श कर बीज आयात निति में परिवर्तन करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्राप्त सुझावों के आधार पर बीज विकास संबंधी नई नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और सरकार आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण जारी कर देती है ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन योजनाएं

2308. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौजूदा वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन कितनी योजनाएं चलायी जा रही हैं और उनके लिए कितने धन का आबटन किया गया है ;